

तापमान
अधिकतम :30°C
न्यूनतम : 20°C

सेंसेक्स
80,501.99
24,346.70

कोटा
96,750
98,000

shahtimes2015@gmail.com

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

देहरादून, शनिवार 3 मई 2025 देहरादून संस्करण: वर्ष 24 अंक 270 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

www.shahtimesnews.com

4 जिल कवा 1446 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें E-paper



इजरायल ने दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के निकट किया हमला
विस्तृत खबर देखें-विदेश पर



केसीए पर विवादित टिप्पणी: श्रीलंता पर लगा तीन साल का प्रतिबंध
विस्तृत खबर खेल टाइम्स पर

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राजन एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिया। कोर्ट में मामले को दूसरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोना, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेहस रंग इंडिया और मेसर्स डोटैक्स के ड्राइव ड्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस दिया है। स्पेशल जज विशाल गोपने ने कहा कि किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूँकता है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। 25 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, दाखिल करें।

छह लोगों के पाकिस्तान डिपोर्टेशन पर सुप्रीम रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर के अहमद तारिक बट्ट के परिवार के 6 सदस्यों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी। कहा कि जब तक इन लोगों के आईडीटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई नहीं हो जाते, तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए। दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। बट्ट परिवार को भी देश छोड़ने का नोटिस मिला। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस एन. कोटियर सिंह को बेंच ने परिवार को यह स्वतंत्रता दी कि यदि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदेश से खुश नहीं हैं, तो जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में दिया कोर्ट का आदेश मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए।

जम्मू-कश्मीर के रामबन में बादल फटा, एनएच-44 बंद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के रामबन में शुक्रवार को बादल फट गया। सड़क पर मडस्लाइडिंग (कोचडू) के चलते जम्मू-श्रीनगर हाईवे (एनएच-44) दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाईवे क्लियर हुआ या नहीं, सोशल मीडिया पर इसका स्टेटस चैक करके ही निकलें। इससे पहले दिल्ली-एनसीआर-यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात आंधी-बारिश और बिजली-पेड़ गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 4-4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली-एनसीआर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट से 200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। 3 को डायवर्ट भी करना पड़ा। 2 को जयपुर और एक को अहमदाबाद में लैंड करवाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरट करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन नार्मल है। दिल्ली एयरपोर्ट से रोज करीब 1,300 उड़ानों की आवाजाही होती है। इससे पहले गुरुवार को परिचम बंगाल के संदकफू में ताजा बर्फबारी हुई। जम्मू में भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

गंगा एक्सप्रेस-वे पर गरजे भारतीय सेना के विमान

शाहजहांपुर। उप्र में शाहजहांपुर के जलालाबाद में बनी हवाई पट्टी पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग ट्रायल करते हुए अपना दम दिखाया।

शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर साढ़े तीन किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। यह देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है, जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात में उतर सकेंगे। भारतीय वायुसेना के जंगी जहाजों ने शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। शाहजहांपुर स्थित साढ़े तीन किलोमीटर एयर स्ट्रिप पर राफेल, मिराज और जगुआर ने एयर शो किया। इन लड़ाकू विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो प्रैक्टिस

की। इस एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को बैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। मेरठ से प्रयागराज तक जोड़ने वाले निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का बदायूं से लेकर प्रयागराज तक 464 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का निर्माण अग्रणी औद्योगिक समूह अदाणी ग्रुप के द्वारा

किया जा रहा है। बदायूं से हरदोई तक 151.7 किमी, हरदोई से उन्नाव तक 155.7 किमी और उन्नाव से प्रयागराज तक 157 किमी के तीन समूहों का निर्माण कर रहा है, जिसे

आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे का लगभग 80 प्रतिशत से ऊपर काम पूरा हो गया है। जलालाबाद तहसील के गांव पीरू के पास गंगा एक्सप्रेसवे से 3.5 किलोमीटर लंबी आधुनिक नवनिर्मित नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी पर शुक्रवार को मौसम खराब होने के



पाक पीएम शहबाज का यूट्यूब चैनल ब्लॉक

पाक ने दो दिन बाद खोला वाघा बॉर्डर, 21 पाक नागरिक लौटे

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिए हैं।

इस बीच, पाकिस्तान ने 2 दिन बाद शुक्रवार को वाघा बॉर्डर खोल दिया है। 30 अप्रैल से बॉर्डर बंद कर दिया था। इसके बाद कई पाक नागरिक स्वदेश नहीं लौट पाए थे। शुक्रवार को 21 पाक नागरिकों को देश लौटने की इजाजत दी गई। ये लोग बीजा सरसैंड होने के बाद भारतीय सीमा में फंसे थे। पहलगाम को बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकीयों की गोलीबारी में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। पहलगाम को बैसरन घाटी में एनआईए और फॉरेंसिक टीम शुक्रवार को जांच करने पहुंची। इंटीलजेंस सूत्रों ने बताया कि



चार क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी किए बंद, नौ को वापस लेने से किया इन्कार, बैसरन में NIA जांच जारी

पहलगाम हमले के बाद इंडियन सिस्टम पर 10 लाख साइबर अटैक, वेबसाइट व पोर्टल्स को टारगेट किया

सैन्य प्रतिष्ठानों की वेबसाइट हैक करने की पाकिस्तान की कोशिश लगातार विफल नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद भारत की घेराबंदी से हताश पाकिस्तान भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की वेबसाइटों को हैक करने की निरंतर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसियां इन कोशिशों को निरंतर विफल कर रही हैं। सुरक्षा सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि भारत द्वारा निरंतर उठाए जा रहे कदमों से बौखलाए पाकिस्तान प्रायोजित हैकर समूह, 'साइबर ग्रुप एचओएएक्स1337' और 'नेशनल साइबर क्यू' भारतीय वेबसाइटों पर निरंतर साइबर हमले कर रहे हैं।

नैनीताल: दुष्कर्म के आरोपी के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर

शाह टाइम्स ब्यूरो

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उस्मान व रुक्नुत वासियों को बड़ी राहत मिली है। अब नगर पालिका मोहम्मद उस्मान व अन्य को अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिए गए नोटिस को वापस लेगी। नगर पालिका ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर अपनी गलती स्वीकार की है।

मोहम्मद उस्मान के अधिवक्ता डा. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने नगर पालिका नैनीताल द्वारा मोहम्मद उस्मान को दिए नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व 15 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन नगर पालिका ने केवल तीन दिन का समय

नैनीताल हाईकोर्ट ने दी राहत, पालिका व पुलिस को लगाई फटकार

दिया जबकि आरोपी जेल में है। इसके अलावा क्षेत्र के कई दर्जन अन्य लोगों को नोटिस दिए हैं। यह अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। इस मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की स्पेशल बेंच बनी थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रथम व द्वितीय कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान तीन दिन का समय दिए जाने के नोटिस पर नगर पालिका ने अपनी गलती

वैदिक मंत्रोच्चार व विधि विधान से खुले बाबा केदार के कपाट



शाह टाइम्स ब्यूरो

रुद्रप्रयाग। पौराणिक परंपराओं, रीति-रिवाजों व विधि-विधान के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी भगवान केदारनाथ के कपाट शुक्रवार प्रातः सात बजे आम भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के साक्षी बीस हजार से अधिक भक्त बने। कपाट खुलने के बाद समाधि में लीन बाबा केदार को जागृत किया गया और फिर विशेष पूजा-अर्चना की गई। अब भक्त धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शनों का पुण्य अर्जित कर सकते हैं।

शुक्रवार प्रातः सात बजे केदारनाथ भगवान के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर समिति के अधिकारी-कर्मचारियों की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग और पुजारी बागेश लिंग ने कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी। इस दौरान सम्पूर्ण केदारनाथी जय श्री केदार के उदघोषों से गुंज उठी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और

कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहे 20 हजार से अधिक भक्त
पहली पूजा पीएम मोदी के नाम की हुई संपन्न
कपाट खुलने की मुख्यमंत्री धामी ने दी देशवासियों को बढ़ाई

शांति का कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को इस पल की प्रतीक्षा रहती है। केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। हमारे राज्य के लिए यह उत्सव का समय है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार से सभी यात्रियों की मंगलमयी यात्रा की प्रार्थना की।

क्या आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है?

बैंक से सम्पर्क करें

बैंक खाता सक्रिय करने के लिए अपना केवाईसी अपडेट करवाएं।

» दो वर्षों से अधिक समय से बैंक खाते में लेनदेन न होने पर वो निष्क्रिय हो जाता है।

» अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर या वीडियो केवाईसी के द्वारा अपना केवाईसी अपडेट करवाएं।

आरबीआई कहता है... जानकार बनिए, सतर्क रहिए!

अधिक जानकारी के लिए, 14440 पर मिस्ड कॉल दें या <https://rbikehtahal.rbi.org.in/ia> पर जाएं फ्रीडबैक देने के लिए, rbikehtahal@rbi.org.in को लिखें

जनहित में जारी भारतीय रिजर्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

जॉन्डिस क्योर

HEALTHY WITH CARE

लिबर का जिगरी दोस्त

आप को भी जॉन्डिस क्योर
जॉन्डिस क्योर की जगह
एवांजेलिस्ट लिबर किजिए
एवं हमें हमारे की
लाभ होने है मुझे

आप के डिप्ट एजेंट हैं

मुफ्त मेंफोन कॉल कर पाउगलम।

86 8484 5757 moficoinc.com

वन क्षेत्र में ईको टूरिज्म की संभावनाएं तलाशी जाएं: मुख्य सचिव

का आवश्यकता पर बल दिए। आईएचएम देहरादून के प्रधानाचार्य डॉ. शिव मोहन ने संस्थान की उपलब्धियाँ, वैश्विक प्लेसमेंट और प्रशिक्षण गुणवत्ता को रेखांकित किया। इस अवसर पर वन मंत्रालय की सूबोध उनियाल, पर्यटन सचिव सिम्रन कुर्वी, अपर सचिव अर्चना रूहेला आदि उपस्थित रहे।

बैठक में उत्तराखंड की ओर कृषि सचिव डॉ सुरेंद्र नारायण पांजा, कृषि एवं उद्यान विभाग के महानिदेशक राजवीर सिंह चौहान, असिस्टेंट सचिव डॉ अनंद श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

[illegible]

पारम्परिक शिल्पकारों व कारीगरों का हो कौशल विकास : डीएम

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। जिलाधिकारी कमेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत परम्परिक शिल्पकारों तथा कारीगरों के आर्थिक उन्नयन हेतु सभी अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी पारम्परिक शिल्पकारों तथा कारीगरों को चिन्हित करते हुए उनके कौशल विकास हेतु गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, इच्छुक व्यक्तियों को आसानी से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने, टूल किट सहायता दिलाने तथा डिजिटल टून्डेशन हेतु जागरूक करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने जनपद के उच्च गुणवत्ता के सामान को ई-मार्केट से जोड़ने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पीएम विश्वकर्मा योजना



के तहत संचालित ट्रेड्स में से जिस ट्रेड में कम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस पर विशेष फोकस करते हुए अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है, साथ ही सीएससी सेंट्रों द्वारा अप्रार व्यक्तियों के फार्म न भरने के दिशा निर्देश भी दिए साथ ही पीएम विश्वकर्मा की मोटिंग हर महीने कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक उद्योग उत्तम कुमार

तिवारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का प्रशिक्षण देने के साथ ही पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पहुँचाने तथा कारीगरों एवं शिल्पकारों को उनके क्षेत्र में ही प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण केन्द्र बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का डाटा अधिशासी अधिकारियों की भांति खण्ड विकास अधिकारियों के डेशबोर्ड पर भी दिखने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारम्भ तथा समापन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि यों एवं उच्चाधिकारियों को बुलाने

के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक उत्तम कुमार तिवारी ने बताया कि स्टेज 2 (डीआईसी) इस वर्ष अभी तक 2569 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 2257 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। जनपद में फिलहाल 07 सेंटर ट्रेनिंग का कार्य कर रहे हैं। बैठक में सभी स्ट्रेकहोल्डर को पीएम विश्वकर्मा योजना के सफल संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बताया कि इस योजना के तहत अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता और कारीगरों को अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने, नई तकनीकी हासिल करने तथा बेहतर उत्पाद तैयार करने में मदद दी जाती है। इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री शोभाग्राम प्रजापति, मुख्य विकास अधिकारी आकाश कोण्डे, वीडोओ सुमन कोटियाल, पवन सिंह नेगी, जोनर सिंह,आलोक गंगेश, एलडीएम संजय संत, एसएनए नगर निगम ऋषभ उनियाल,डाॅ. प्रदीप कुमार सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मेयर किरण जैसल ने हरी झंडी दिखाकर दवा स्प्रे टैंकरों को किया रवाना



शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। गर्मी के मौसम को देखते हुए नगर निगम द्वारा दवा स्प्रे टैंकरों को शुरूआत की गयी है। मेयर किरण जैसल ने रानीपुर मोड़ स्थित कैंप कार्यालय पर हरी झंडी दिखाकर टैंकरों को रवाना किया। मेयर किरण जैसल ने बताया कि शहर के लोगों द्वारा लगातार दवा छिड़काव की मांग की जा रही थी। गर्मी के मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। पानी जमा होने से डोंगू मच्छरों के पतनने की आशंका भी रहती है। टैंकरों के

माध्यम से सभी बाड़ों में दवा का स्प्रे किया जाएगा। जिससे मच्छरों का प्रकोप कम होगा और मच्छर जनित रोगों से बचाव करने में भी मदद मिलेगी। मेयर ने सभी से सफाई व्यवस्था में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास सफाई का ध्यान रखने और पानी जमा न होने दे। इस दौरान सहायक नगर अधि कारी ऋषभ उनियाल, सीनियर सेनेटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत चौधरी, कार्यवाला प्रभारी आदित्य तेवर और भाजपा कार्यवाही मौजूद रहे।

सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में स्कूल के सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कर्मी की मौत के बाद परिवार व आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन स्कूल प्रशासन व पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराना जरूरी नहीं समझा। जिसके बाद से शहर भर में स्कूल की कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्कूल को छुट्टी तक नहीं की। वहीं मौत के भी अलग-अलग कारण सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुरुआत सुबह बारिश के बीच ज्वालापुर के सुभाषनगर में स्थित एक स्कूल के करीब 40 वर्षीय सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुरक्षा कर्मी को स्कूल कैंपस में पड़ा देख परिजनो के होश उड़ गए। जिसके बाद उसको रानीपुर मोड़ स्थित अस्पताल में लें जाया गया। जहां डॉक्टरों ने

उसे मृत घोषित कर दिया। कर्मी की मौत के मामले में दो अलग-अलग वजह निकल कर सामने आई हैं। पहली वजह करंट लगाना बताया जा रहा है तथा दूसरी वजह बारिश के पानी में पैर फिसलना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। लेकिन पुलिस व स्कूल प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराना जरूरी नहीं समझा। यहां तक कि सुरक्षा कर्मी की मौत खडे हो रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने चलता रहा और सुरक्षा कर्मी के रूम में ही दिन भर उसका शव पड़ा रहा। स्कूल प्रशासन मामले को दबाने में लगा रहा है जिसके बाद से कर्मी की मौत को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ग्रह घटना दिन भर शहर में चर्चा का विषय बनी रही। वहीं एसएसआई ज्वालापुर नितिन चौहान ने बताया कि मामले एक्सीडेंटल मौत का प्रतीत होता है। पुलिस को मामले की जांच के लिए मौके पर भेजा गया था। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए मना किया।

चौधरी चरण सिंह पुनः चुने गए वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। चौधरी चरण सिंह लगातार चौथी बार वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष चुने गए हैं। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर ज्वालापुर इंटर कालेज प्रांगण में देर शाम आयोजित संगठन की बैठक में चौधरी चरण सिंह को सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष चुना गया। साथ ही निवृत्तमान कार्यकारिणी को ही अगले कार्यकाल के लिए मनोनीत किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और सरस्व्यों ने चौधरी चरण सिंह को शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व में संगठन द्वारा जनता और वरिष्ठ जनों के कल्याण हेतु किए गये कार्यों की सराहना की। बैठक में सभी ने शिकागो में अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हुए श्रमिकों और 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि

भी दी गयी। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि वरिष्ठ जनों और जनता की समस्याओं को लेकर वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन का संघर्ष पूर्व की भांति जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश सरकार के साथ है। सरकार को आतंकवादियों और उनके मददगार पाकिस्तान को करारा सबक सिखाना चाहिए। बैठक में गिरधारी लाल, रामबचन गुप्ता, संतराम, सुखवीर सिंह, शिवबचन, प्रेम कुमार, एसएन बत्रा, एपी गौड़, चौपाल सिंह, विद्यासार, हरदयाल अरोड़ा, सुंदरलाल, शिवकुमार, अशोक पाल, एससीएस भास्कर, डा. रमेश कुमार, केंपी शर्मा, पीसी धीमान, बाबूलाल, शिवचरण, महेंद्र शर्मा, सतपाल चंदना, महेंद्र सिंह, सुभाष ग्रावर, महेशचंद त्यागी, जगराम सिंह आदि वरिष्ठजन मौजूद रहे।

गंगा सभा के पदाधिकारियों ने किया प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को सम्मानित

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। हस्की पैड़ी प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा ने प्रेस क्लब हरिद्वार के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों अध्यक्ष धर्मेश चौधरी, महासचिव दीपक मिश्रा सहित समस्त कार्यकारिणी को सम्मानित किया। बृहस्पतिवार को देर शाम हस्की पैड़ी स्थित श्री गंगा सभा कार्यालय में प्रसिद्ध कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी की मौजूदगी में गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महासचिव तमय वशिष्ठ ने गंगाजली, प्रसाद और पटका भेंटकर प्रेस क्लब पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मां गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी ने कहा कि मोक्षदायिनी गंगा हरिद्वार की पहचान है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार आते हैं और गंगा के पानन जल में स्नान कर मोक्ष की पाप्मा करते हैं। पुंडरीक गोस्वामी ने कहा कि हस्की पैड़ी का ब्रह्मकुंड वह स्थान है, जहां आने के लिए देवता भी लालचलित रहते हैं। इसी गंगा के पानन तट पर कुंभ और अर्द्धकुंभ जैसे महत्वपूर्ण संपन्न होते हैं। वे परम सौभाग्यशाली है कि उन्हें गंगा के पानन तट पर



कथा करने का अवसर मिला है। इसके लिए वें गंगा सभा के पदाधि कारियों का आधार व्यक्त करते हैं। पुंडरीक गोस्वामी ने कहा हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप विद्य है। गंगा जल में चरण स्पर्श करने पर विष्णु, आचमन संकल्प में ब्रह्मा और स्नान के उपरांत केशों से जल बहने पर शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसे पवित्र स्थान पर गंगा स्नान और ससंग श्रवण का निराला, संजय रावल एवं वर्तमान कार्यकारिणी में सचिव डा. हिमांशु द्विवेदी, समारोह सचिव आशु

पर भजन संध्या कर परम आनंद की अनुभूति हो रही है और इसके लिए वे बार- बार हरिद्वार आने के लिए तैयार है। इस दौरान प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मेश चौधरी, महासचिव दीपक मिश्रा, प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष शिवशंकर जायसवाल, स्थाई सदस्य एवं एनयूजे आई के प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त पाण्डेय, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष, गुलशन नेव्यर, वृजेन्द्र हर्ष, डा. रजनीकांत शुक्ला, संजय आर्य, दीपक नोटियाल, संजय रावल एवं वर्तमान कार्यकारिणी में सचिव डा. हिमांशु द्विवेदी, समारोह सचिव आशु

शर्मा, विकास कुमार झा, सुनील पाल, संजय चौहान, डा.प्रविन्द्र कुमार, सुनील मिश्रा, सुनील पाल, राहुल वर्मा, पुलकित शुक्ला, अनमोल कुमार को पटका, मां गंगा का प्रसाद और गंगाजली भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तमय वशिष्ठ, स्वागत मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणि, सचिव वीरेंद्र कौशिक, प्रचार सचिव शैलेश मोहन, सचिव उज्जवल पंडित, पुंडरीक गोस्वामी के पिता विजय कृष्ण गोस्वामी, पत्नी रेणुका गोस्वामी सहित अन्य मौजूद रहे।



शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। श्री जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य स्मारक समिति के तत्वाधान एवं समिति के महामंत्री श्रीमहंत देवानंद सरस्वती महाराज के संयोजन में शंकराचार्य चौक पर जगद्गुरु शंकराचार्य के श्री विग्रह के पूजन के पश्चात हरिहर आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने संतजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। शंकराचार्य चौक पर श्री विग्रह पूजन के समय म.म. स्वामी प्रबोधानंद गिरि, म.म. डा.

प्रेमानंद, भारत माता मंदिर के श्रीमहंत एवं निर्जनी अखाड़े के म.म. स्वामी ललितानंद गिरी महाराज, म.म. राधेश्वरानंद सरस्वती, म.म. गिरधर गिरी, शिवडेल स्कूल के संस्थापक स्वामी शरद पुरी, दयानंद तीर्थ, स्वामी केशवानंद, स्वामी विवेकानंद महाराज, स्वामी सहजानंद, स्वामी हंसानंद, स्वामी उमानंद गिरी, स्वामी कृष्णानंद, स्वामी महेशपुरी सहित संत महंत उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा में स्वामी देवानंद सरस्वती महाराज के संचालन में उपस्थित महामंडलेश्वर व संत जनों ने जगतगुरु आद्य शंकराचार्य भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

5.10 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

पथरी। पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक नशा तस्कर को 5.10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार गुरुवार देर शाम को ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत चलाए गए अभियान को सफल बनाने के लिए फेरपुर चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जिसमें ध नपुरा पीर के पास बाइक पर सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर युवक के पास से लगभग 5.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई पृष्ठताछ में युवक ने अपना नाम सोएव पुत्र मुन्तजिर निवासी



धनपुरा बताया और स्मैक के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया आरोपी को खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है।बाइक को सीज किया गया है।

एसओ पथरी मनोज नोटियाल ने बताया एक युवक को लगभग 5. 10 ग्राम स्मैक के साथ धनपुरा पीर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है।

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी द्वारा किए गए हमले में निर्दोष पर्यटकों को हत्या के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के बैनर तले जनपद हरिद्वार के शिक्षक कर्मचारियों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इसके संदर्भ में शहीद भगत सिंह चौक पर सभी शिक्षक कर्मचारियों एकत्रित हुए एवं सभी के द्वारा कैंडल जलाकर कतार के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से रानीपुर मोड़ होते हुए प्रेम नगर आश्रम घाट तक कैंडल मार्च निकाला गया, घाट पर उन्होंने हमले में शहीद भारतीयों के नाम के दिए जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा में प्रवाहित किए। मार्च के दौरान उपस्थित गढ़वाल मंडल अध्यक्ष विकास कुमार

शर्मा द्वारा बताया गया कि संपूर्ण भारत के शिक्षक कर्मचारी सरकार

अध्यक्ष सुखदेव सेनी द्वारा आशा की गई कि भविष्य में इस प्रकार

कार्यवाही की जानी चाहिए। जनपद मंत्री दीपक चौहान द्वारा बताया



के साथ हैं सरकार दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करें। जनपद

के आतंकी हमलो की पुनरावृत्ति ना हो जिसके लिए दोषियों पर कड़ी

गया कि देश संपूर्ण शिक्षक एवं कर्मचारियों की संवेदनाएँ शहीद परिवारों के साथ हैं। कैंडल मार्च में उपस्थित सभी कर्मचारी, एवं शिक्षकों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की एक स्वर में

कड़ी निंदा की , और सरकार से मांग की कि सरकार को ठोस कदम आतंकियों के विरुद्ध उठाने चाहिए जिससे इस प्रकार के हमले की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो सके । जनपद प्रभारी सदा शिव भास्कर ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को तत्काल आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही अमल में लानी चाहिए। इस दौरान गढ़वाल मंडल उपाध्यक्ष वीर सिंह पवार, संगठन मंत्री सुरेश पाल सिंह, मनोज बरछीवाल, मदनपाल सिंह, ज्योतिराम, सुनीता जोशी, सरिता मलिक, विनोद यादव राकेश पंवार, दर्शन सिंह पंवार, ललित मोहन जोशी अश्वनी चौहान, रविंद्र रोड खीमानंद भट्ट, अखिलेश धारीवाल, निरोध चौधरी, शैलेन्द्र गौड़, जॉनी प्रसाद, कुलदीप सेनी, मनोज चंद, सचिन पंवार, तारा सिंह, मंत्री चंद्रकांत बिष्ट, सुनीता जोशी, श्रद्धा हिन्दू, यादोराम, पंकज बिश्नोई, मुकेश चौहान, जितेंद्र चौधरी, तेजवीर सेनी, बबलू सिंह आधाना, सोमपाल सिंह, कुलदीप सिंह, कृष्ण पाल सिंह, सतेंद्र कुमार, राजीव शर्मा, वृजमोहन मौर्य चरण सिंह, अनिल कुमार शर्मा, आदि शामिल रहे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस पर खरी उतरी ‘धाकड़’ धामी की सरकार वरुण चौधरी के कार्यकाल में हुई खरीद-फरोख्त के मामलों की उठ रही जांच की मांग

डिस्पेंसरी के आवंटन को भी जल्द किया जा सकता है निरस्त, एमएनए हुए सख्त जिस सविदा कर्मी को हानी थी सेवा समाप्त, उसका कर दिया स्थानांतरण, उठ रहे सवाल?

आरिफ अंसारी

हरिद्वार। नगर निगम हरिद्वार के बहुचर्चित हो चले भूमि घोटाले की जांच प्रारम्भ होते ही उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस प्रकार भ्रष्ट अधि कारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है उससे निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सराय स्थित निगम के कूड़ा प्लांट से लगती हुई भूमि निगम प्रशासन द्वारा बिना कोई प्रकाशन या विज्ञापित जारी किये हुए खरीदी थी। जिसको लेकर पिछले दिनों बोर्ड की बजट बैठक के दौरान पार्षदों द्वारा जमकर हंगामा किया गया था। यही नहीं खड़खड़ी में नगर निगम के स्थायित्व वाली डिस्पेंसरी को बिना कोई विज्ञापित प्रकाशित कराये मात्र 8.5 हजार मासिक करिये पर दिये जाने को लेकर भी काफी हंगामा बोर्ड बैठक के दौरान हुआ था अब जहां एक ओर भूमि घोटाले में बड़ी कार्यवाही

हुई है तो वहीं दूसरी ओर डिस्पेंसरी को किराये पर दिये जाने के मामले में आवंटन प्रक्रिया निरस्त करने को लेकर मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार कनकर कस चुके हैं। भूमि खरीद का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए जांच के आदेश जारी किये थे। अब बृहस्पतिवार को इस प्रकरण में प्रथमदृष्टया गंभीर अनियमितता पाये जाने के दृष्टिगत उक्त अनियमितता में प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाये गये प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार रवीन्द्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता, नगर निगम, हरिद्वार आनन्द सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक, नगर निगम, हरिद्वार लक्ष्मीकांत भट्ट एवं सविदा मानचित्रकार नगर निगम, दिनेश चन्द्र काण्डपाल, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

मानचित्रकार ने अवर अभियंता बनकर किए फाइल पर हस्ताक्षर

15 हजार मासिक वेतन पाने के बावजूद पाँश इलाके में निर्मित आवास बना चर्चा का विषय

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। नगर निगम के भूमि घोटाले में निलम्बित हुए अधि कारियों की फहरिस्त में शामिल सविदा मानचित्रकार दिनेश चन्द्र कांडपाल को लेकर शुक्रवार को पूरे दिन निगम में चर्चोंओं का दौर चलता रहा। भूमि घोटाले में दिनेश चन्द्र की सल्लिप्ता को देखते हुए अपर सचिव गौरव कुमार की ओर से जारी आदेश में दिनेश चन्द्र कांडपाल को लोहाघाट अटैच करते हुए निलम्बित किया गया। जबकि दिनेश चन्द्र स्थाई कर्मचारी न होकर सविदा मानचित्रकार के पद पर निगम में तैनात था। भूमि घोटाले की पत्रावली में दिनेश चन्द्र सविदा कर्मचारी को अवर

आकाओं को खुश करने के लिए अवर अभियंता बन बैठा सविदा मानचित्रकार

नगर आयुक्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं? जब दिनेश चन्द्र कांडपाल अभियंता न होकर मानचित्रकार के पद पर कार्यरत था तो आखिर कैसे दिनेश चन्द्र को अवर अभियंता बना दिया गया और दिनेश चन्द्र ने भी भूमि खरीद प्रोजेक्ट को फाइल पर अवर अभियंता के तौर पर ही अवरने हस्ताक्षर किये। वह भी तब जब नगर निगम हरिद्वार में दो-दो

अवर अभियंता पूर्व से ही तैनात चले आते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि स्थाई अभियंता होने के बावजूद आखिर किस आधार पर सविदा मानचित्रकार को अभियंता दर्शकर सहमति ली गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्य नगर आयुक्त गौरव चौधरी की गुड बुक में शामिल दिनेश चन्द्र कांडपाल को निर्माण कार्यों के संबंध में 20 बाड़ों का प्रभार भी दिया गया था। बताया जा रहा है कि तिकड़म बाजी में माहिर दिनेश चन्द्र कांडपाल को भले ही नगर निगम से 15 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता रहा हो लेकिन हरिद्वार के पाँश इलाके में निर्मित उनका आवास पूरी कहानी बयान करने के लिये काफी हैं।

का सेवा विस्तार समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध सविल सर्विसेज रगुलेशन के अनुच्छेद 351(ए) के प्राविधानों

वक्फ संशोधन विधेयक सरकार का ऐतिहासिक व मुस्लिम हित में लिया निर्णय : डा. शालिनी

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। भाजपा नेत्री एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की संयोजिका डा. शालिनी अली ने प्रेस क्लब में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए

निर्णय-निर्माण की मुख्यधारा में लाने का स्वागत योग्य और साहसिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वक्फ संपत्तियों का अपने हित में प्रयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए संशोधन से वक्फ संपत्तियों के

कहा कि वक्फ संशोधन का ऐतिहासिक और समाजहित में लिया गया निर्णय है। डा. शालिनी अली ने कहा कि वक्फ एक पवित्र सामाजिक और धार्मिक संस्था है। जिसका मूल उद्देश्य मुस्लिम समाज के गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की व्यवस्था करना है। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्षों से यह संस्था लैंड माफियाओं, प्रेष तत्वों और लैंड जिहाद जैसे गतिविधियों का शिकार रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों में दो महिलाओं की भागीदारी अब अनिवार्य की गई है, जो मुस्लिम महिलाओं को



दुरुपयोग पर रोक लगेगी और गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने 'बत्ती गुल' कर वक्फ कानून को प्रयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए संशोधन से वक्फ संपत्तियों के राजनीतिक स्टेट बनाते हुए कहा कि कुछ लोग अपने हित के लिए समाज को गुमराह कर बत्ती गुल जैसे आयोजन कर रहे हैं।

सम्पादकीय

शनिवार , 3 मई 2025

प्रेस की आजादी पर संकट

दुनिया में प्रेस की आजादी को लेकर पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ हर साल रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट विदाउट बार्डर्स (आरडब्ल्यूबी) 2025 में उसने दुनियाभर के 180 देशों के विषय में प्रेस की आजादी के बारे में बताया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 151वाँ रैंक में रखा है। यह रैंक बताती है कि भारत में पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत ने इसमें सुधार किया है। पिछले बार भारत की रैंकिंग 159 थी। दिलचस्प बात यह रह है कि अमेरिका जैसे देश जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षक बनता है वहा भी प्रेस की आजादी में गिरावट की बात सामने आ रही है। इंडेक्स में अमेरिका को 57वें पायदान पर रखा है। जबकि पिछले वर्ष उसकी रैंकिंग 55 थी। रिपोर्ट कहती है कि यह गिरावट डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद हुई है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि वह 42 देश जिनमें दुनिया की आधी आबादी रहती है वहां प्रेस की स्थिति बेहद गंभीर है और वहां प्रेस को लगभग न के बराबर आजादी है। रिपोर्ट में जहां नावें को पहले स्थान पर रखा है तो वही सबसे निचले स्थान पर इरीट्रिया देश है। इस तरह भारत की स्थिति भूटान, पाकिस्तान, चीन, रूस, सीरिया, फलस्तीन, अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया से बेहतर है। निश्चित रूप से प्रेस की आजादी वर्तमान समय में काफी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राजनीतिक तो है ही बल्कि आर्थिक भी है। रिपोर्ट में इसी तरफ इशारा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर का मीडिया फंडिंग की कटौती से जूझ रहा है। सूचना के संसाधनों को गूगल, एप्पल, फेसबुक, एमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों के दबदबे की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो पहले विज्ञापन मीडिया आउटलेट्स को मिलते थे अब वह इनके पास जा रहे है। रिपोर्ट बताती है कि भारत सहित कुछ देशों में मीडिया आउटलेट्स नेताओं और बिजनेसमैन से मिलने वाली शर्शर्त फंडिंग की वजह से अपना अस्तित्व बचाए हुए है कहने का मतलब साफ है कि मीडिया दिन-प्रतिदिन अपनी साख खो रहा है जिसके लिए वह कभी जाना जाता था और यह सब इस लिए हो रहा है क्योंकि इस पर अब राजनेताओं और पूँजीपतियों का दबाव बन चुका है। चीन, वयतनाम जैसे देशों में तो मीडिया सरकार के मुखपत्र का काम करता है। हाल ही में हम देख रहे है कि फलस्तीन में किस तरह मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है अब तो 200 से अधिक पत्रकार वहां अपनी जान गंवा चुके है। इजरायल ने अपनी बमबारी से वहां तमाम मीडिया के ऑफिस बर्बाद कर दिए है। कोई भी देश अपनी मनमानी के चलते किसी भी विदेशी मीडिया को अपने यहां काम करने से रोक देता है। इस तरह हम कह सकते है कि आज के दौर में मीडिया अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है यह स्थिति ठीक नहीं है। सही सूचना आम लोगों तक पहुंचे इसकी व्यवस्था होना बेहद जरूरी है, लेकिन यह तभी संभव होगा। जब मीडिया को शक्ति प्रदान करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाए। जो कि आज दूर की कोड़ी की बात लगती है।

बुजुर्ग परिवार के भावनात्मक स्तंभ

बुजुर्गों के मार्गदर्शन को महत्व देकर उनके बहुमूल्य सानिध्य का आनंद लेना चाहिए, माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, आमतौर पर परिवारों में देखा जाता है कि बच्चे अपने दादा-दादी के साथ बहुत सहज होते हैं, बुजुर्ग परिवार के लिए भावनात्मक स्तंभ की तरह काम करते हैं, जब बुजुर्ग अपने परिवार को फलते-फूलते देखते हैं, तो वे भी शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक और भागदौड़ भरी जिंदगी में वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग, प्रेरणा और मार्गदर्शन युवा पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है, वरिष्ठ नागरिकों के पास जो अनुभव और ज्ञान है, वह युवा पीढ़ी को जटिल चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है।



द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति

केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है पत्रकारिता की स्वतंत्रता

कलम की आजादी पर कसता शिकंजा

भारत में प्रेस को सदैव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी जाती रही है क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की बहुत अहम माना गया है लेकिन विदुष्यना है कि विगत कुछ वर्षों से यहा भी प्रेस स्वतंत्रता के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। इसीलिए प्रतिवर्ष 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है। कलम को तलवार से भी ज्यादा ताकतवर और तलवार की धार से भी ज्यादा प्रभावी इसीलिए माना गया है क्योंकि इसी की सजगता के कारण न केवल भारत में बल्कि अनेक देशों में पिछले कुछ दशकों के भीतर बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो सका, जिसके चलते बड़े-बड़े उद्योगपतियों, नेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को एक ही झटके में अंश से फर्श पर आना पड़ा। यही कारण हैं कि समय-समय पर कलम रूपी इस हथियार को मोथरा बनाने या तोड़ने के कुचक्र होते रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में सच की कीमत कुछ पत्रकारों को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है। पिछले दशकों में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में स्थितियां काफी बदल गई हैं। आज दुनियाभर में पत्रकारों पर राजनीतिक, अपराधिक और आतंकी समूहों का सर्वाधिक खतरा है और भारत भी इस मामले में अछूता नहीं है। विदुष्यना है कि दुनियाभर के न्यूज रुम्स में सरकारी तथा निजी समूहों के काराग भय और तनाव को स्वतंत्रता को लेकर जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, वे सदैव चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि कुछ देश इस रिपोर्ट में जारी किए जाने वाले आंकड़ों को पूर्वाग्रह से प्रेरित बताकर खारिज भी करते रहे हैं।



‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ एक ऐसा गैर-लाभकारी संगठन है, जो विश्वभर के पत्रकारों पर हमलों का दस्तावेजीकरण करने और मुकाबला करने के लिए कार्यरत है और प्रतिवर्ष ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ अर्थात् ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक’ नामक रिपोर्ट पेश करता है। ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019’ में उसने भारत सहित विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया था कि किस प्रकार विश्वभर में पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल गई है, जिससे दुनियाभर में पत्रकारों में डर बढ़ा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के मुताबिक भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पर है जबकि 2023 में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर और 2022 में 150वें पायदान पर खड़ा था। यह रिपोर्ट प्रेस स्वतंत्रता के लिए भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट का संकेत देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के साथ व्यवहार के लिए ‘संतोषजनक’ माने जाने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है लेकिन ऐसी संख्या भी कम नहीं है, जहां स्थिति ‘बहुत गंभीर’ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी दुनियाभर के देशों की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत जहां जहां 2024 में 2023 के मुकाबले दो पायदान ऊपर चढ़ा,

वहीं 2023 में 2022 के मुकाबले 11 पायदान नीचे गिरा था और 2022 में भी 2021 की रैंकिंग के मुकाबले 8 स्थान नीचे फिसल था। 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को सूची में शीर्ष 10 देशों में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, एस्तोनिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्विटजरलैंड तथा जर्मनी शामिल हैं। भारत के लोकतंत्र को तो दुनिया का सबसे सफल और बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहीं अगर नावें जैसा छोटा सा देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में लगातार शीर्ष स्थान पर विराजमान है तो यह स्थिति भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए सही स्थिति नहीं है। ऐसे में हमें गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है कि हम इस मामले में वर्ष दर वर्ष क्यों फिसल रहे हैं? प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में यह गिरावट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आने का सीधा और स्पष्ट संकेत यही है कि लोकतंत्र की मूल भावना में अपविध्यन्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार निहित है, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। समाज में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ माना गया है लेकिन पिछले कुछ वर्षों

अंततः देश में जाति जनगणना: प्रतिनिधित्व या पुनरुत्थान

भारत में दशकों से केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती होती रही है, जबकि अन्य जातियाँ नीति निर्माण में अदृश्य रहें। जाति जनगणना केवल गिनती नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की नींव है। बिना सटीक आंकड़ों के आरक्षण, योजनाएं और संसाधन वितरण अधूरे रहेंगे। विरोध करने वालों को डर है कि उनके विशेषाधिकार चुनौती में पड़ सकते हैं। लेकिन यह गिनती वाँचतो की दृश्यता और भागीदारी सुनिश्चित करने का औज़ार है, न कि समाज को तोड़ने का। जब नीति जाति पर आधारित हो, तो डेटा भी होना चाहिए।

भारत को जातियों में बांटा गया, लेकिन उसे जोड़ने की कोशिश कभी पूरी ईमानदारी से नहीं हुई। संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया, मगर समान अवसर की नींव जातिगत असमानता को पहचाने पर ही टिकती है। इसी बुनियाद पर जब आज जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है, तो सवाल खड़ा होता है क्या यह सामाजिक न्याय का औज़ार है या समाज को और अधिक खाँचों में बाँटने की कवायद।

भारत में पिछली बार व्यापक जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद, आजादी के बाद के राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में एक आदर्श सामने रखा गया ‘जातिविहीन समाज’। इस आदर्श का आकर्षण था, पर व्यवहार में यह एक तरह की चुप्पी थी। 1951 से लेकर 2011 तक हर जनगणना में केवल अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की गिनती होती रही, बाकी जातियाँ ‘अदृश्य’ रहें। लेकिन अगर नीति आरक्षण आधारित हो, योजनाएं वर्गों के लिए हों, तो आंकड़े क्यों न हों। क्या यह संभव है कि बिना जानकारी के न्यायपूर्ण वितरण हो।

बिहार की जाति आधारित सर्वेक्षण ने एक नई लहर पैदा की। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पहल ने अन्य राज्यों को भी सोचने पर मजबूर किया। एक ओर जातिगत गणना को सामाजिक न्याय की बुनियाद बताया गया, तो दूसरी ओर कुछ वर्गों ने इसे सामाजिक विभाजन का उपकरण कहा। कई राजनीतिक दल इस मांग को समर्थन दे रहे हैं, खासकर वे जिनकी राजनीति वंचित तबकों पर आधारित है। लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका झिझकभरी रही है। केंद्र का कहना है कि यह बेहद जटिल प्रक्रिया है और इसमें सामाजिक तनाव पैदा हो सकते हैं। जाति जनगणना के समर्थन में कई मजबूत तर्क दिए जा रहे हैं। अगर हम यह नहीं जानते कि कौन-सी जातियाँ किस आर्थिक व सामाजिक स्थिति में हैं, तो योजनाएं महज अंदाजों पर चलती रहेंगी। आरक्षण का पुनर्मूल्यांकन करना हो या सामाजिक योजनाओं का लक्ष्य तय करना हो, सटीक आंकड़ों की आवश्यकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनसंख्या कई राज्यों में 40-50 प्रतिशत तक मानी जाती है, जबकि उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सही आंकड़े हों तो नीति ज्यादा न्यायसंगत हो सकती है।

विरोध करने वालों की मुख्य दलील यह है कि जाति जनगणना समाज में जातीय पड़कान को और मजबूत करेगी। इससे सामाजिक एकता को खतरा होगा और राजनीतिक दल केवल जाति कार्ड खेलकर वोट बंटोने लयेंगे। कुछ वर्गों को डर है कि अगर सही आंकड़े सामने आ गए, तो उनका ‘निहित अधिकार’



1951 से लेकर 2011 तक हर जनगणना में केवल अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की गिनती होती रही, बाकी जातियाँ ‘अदृश्य’ रही, लेकिन अगर नीति आरक्षण आधारित हो, योजनाएं वर्गों के लिए हों, तो आंकड़े क्यों न हों, क्या यह संभव है कि बिना जानकारी के न्यायपूर्ण वितरण हो

हैं। अगर हम यह नहीं जानते कि कौन-सी जातियाँ किस आर्थिक व सामाजिक स्थिति में हैं, तो योजनाएं महज अंदाजों पर चलती रहेंगी। आरक्षण का पुनर्मूल्यांकन करना हो या सामाजिक योजनाओं का लक्ष्य तय करना हो, सटीक आंकड़ों की आवश्यकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनसंख्या कई राज्यों में 40-50 प्रतिशत तक मानी जाती है, जबकि उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सही आंकड़े हों तो नीति ज्यादा न्यायसंगत हो सकती है।

विरोध करने वालों की मुख्य दलील यह है कि जाति जनगणना समाज में जातीय पड़कान को और मजबूत करेगी। इससे सामाजिक एकता को खतरा होगा और राजनीतिक दल केवल जाति कार्ड खेलकर वोट बंटोने लयेंगे। कुछ वर्गों को डर है कि अगर सही आंकड़े सामने आ गए, तो उनका ‘निहित अधिकार’ छिन सकता है खू जैसे सवर्ण वर्गों को लगता है कि ओबीसी या दलितों की संख्या के अनुपात में अगर आरक्षण बढ़ा, तो उनके लिए मौके और कम हो जाएंगे। जब बिहार ने अपना जातिगत सर्वेक्षण कराया, तो केंद्र सरकार ने उससे दूरी बनाए रखी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी मांग उठी, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बन सकी। कई बार यह तर्क दिया गया कि यह विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जाति आधारित जनगणना पर सीधे रोक नहीं लगाई, लेकिन कहा कि यह नीति का विषय है और सरकारें अपने विवेक से निर्णय लें।

वंचित समुदायों के लिए जाति जनगणना केवल गिनती नहीं है, यह उनकी दृश्यता का सवाल है। अगर समाज में कोई वर्ग आर्थिक, शैक्षणिक और



पूजिका चौधरी

राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह है कहाँ? कितना है? डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था ‘यदि आपको सुधार करना है, तो पहले तथ्यों को जानिए।’ जातिगत आंकड़े भी ऐसे ही तथ्य हैं। यह आंकड़े केवल आरक्षण तय करने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वरोजगार जैसी नीतियों के लिए जरूरी हैं। आश्चर्य की बात है कि जाति जनगणना जैसे गहन विषय पर मुख्यधारा मीडिया में गंभीर बहस कम होती है। जो बौद्धिक वर्ग खुद को प्रगतिशील मानता है, वह या तो इसे ‘रिग्रेसिव’ बताकर खारिज कर देता है या चुप रहता है। दरअसल, समस्या यह नहीं कि जाति की गिनती हो रही है। समस्या यह है कि जिनमें अपने ‘विशेषाधिकार’ की चिंता है, वे इस गिनती से असहज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल मान लीजिए कि जाति जनगणना होती है और सभी जातियों के आंकड़े सामने आते हैं। अब क्या होगा? क्या सरकारें इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण नीति में बदलाव करेंगी? क्या यह संभव होगा कि किसी जाति की संख्या ज्यादा निकलने पर उन्हें ज्यादा हिस्सेदारी दी जाए? या फिर आंकड़ों को दबा दिया जाएगा, जैसे 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के साथ हुआ? 2011 में हुई एसईसीसी के आंकड़े आज भी सार्वजनिक रूप से अधूरे हैं। सरकारें आती गईं, लेकिन किसी ने इसे पूरी पारदर्शिता से नहीं जारी किया। जाति एक सामाजिक सच्चाई है, जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं। जो सत्ताएं जातिविहीन समाज की बात करती हैं, वे चुनौती टिकाट देने, मंत्रिमंडल गठन, और अफसरों की नियुक्ति में जाति ही देखती हैं तो फिर आंकड़ों से डर क्यों? जाति जनगणना न सामाजिक ट्रटन लाएगी, न समाज की बुनियाद को कमजोर करेगी बशर्ते इसका उपयोग न्यायपूर्ण नीति निर्माण के लिए हो। डर उन्हें है जिनके पास पहले से ही ज्यादा है। जो वंचित हैं, वे तो सिर्फ अपनी मौजूदगी की पुष्टि चाहते हैं। आखिर यह देश सभी जातियों का है तो सभी की गिनती क्यों नहीं?

एक पादप मॉडल का अनदेखा पहलू...

सरसों परिवार (ब्रेसिकेसी) का एक छोटा सा पौधा है थेल क्रैस (Arabis thaliana)। 20-25 से.मी. लंबे इस पौधे में अधिकतर पत्तियां जमीन से सटकर, फूलनुमा आकृति बनाते हुए लगती हैं और बहुत थोड़ी पत्तियां ऊपर तने पर भी लगती हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं। यह पौधा मूलतः यूरेशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। भारत में यह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। यह खाली पड़े मैदान, सड़क किनारे, रेललाइन किनारे, खेतों में, कहीं भी उगता देखा जा सकता है, इसलिए इसे खरपतवार की तरह देखा जाता है, हालांकि कुछ जगहों पर इसे खाया भी जाता है।

स्रोत फील्ड

थेल क्रैस पौधे की कुछ खास बातें हैं। एक तो इसका जीवन चक्र छोटा होता है, अंकुरण से लेकर वापस बीज बनने तक का इसका चक्र 6 हफ्ता में पूरा हो सकता है, यह खरपतवार की तरह आसानी से फल-फूल जाता है, इसका पौधा साइज में छोटा तो होता ही है, साथ ही इसका जीनोम भी सरल होता है। अपनी इन सभी खूबियों के कारण 1900 के दशक से ही पादप विज्ञान में थेल क्रैस पर अध्ययन किए जाने लगे थे। फुलदार पौधों की जेनेटिक, आणविक कार्यप्रणाली को समझने में थेल क्रैस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहला संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण भी इसी पौधे का किया गया था। और तो और, पादप विज्ञान का यह मॉडल या 2019 में चांग ई-4 लैंडर के साथ चाँद की भी सैर कर चुका है। और अब, इस पौधे के एक अनछुए पहलू का अध्ययन कर पादप विज्ञानी रियुशिरो कासाहारा और उनके दल ने इसकी एक ओर खासितव उजागर की है जो खेती के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पता चला है कि (कम से कम) यह पौधा बड़ी चतुराई से अपने सिर्फ उन्हीं बीजांडों तक पोषण पहुंचने देता है

जो निर्धारित हो चुके होते हैं। और, अपने गैर-निर्धारित बीजांड तक पोषण पहुंचने से रोकता है, जिससे पोषण का सदुपयोग होता है और बीज बड़ा बनता है। और, बड़ा बीज यानी पैदावार में वृद्धि, लेकिन अन्य फसलों में बीज कैसे बढ़ा किया जाए? इस पर बात करने के पहले थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं कि शोधकर्ताओं को यह बात पता कैसे चली। दरअसल, कासाहारा यह समझना चाह रहे थे कि पौधे बीज कैसे बनाते हैं? इसके लिए कासाहारा ने थेल क्रैस को अध्ययन के लिए चुना और अपना सारा ध्यान इसके फूल के उस स्थान पर केंद्रित किया जहां कई सारी नलिकाओं (फ्लोएम) के माध्यम से पोषक तत्व पहुंचकर विकासशील भ्रूण को पोषण देते हैं।

नीले रंजक का इस्तेमाल कर उन्होंने इस हिस्से में कैलोस का असर देखा। गौतलब है कि कैलोस पौधों में अस्थायी कोशिका भित्ति बनाकर पौधों के लिए कई काम करता है और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे यह पौधों के घावों को भरने में मदद करता है। पता चला कि फ्लोएम के अंतिम छोर पर बीजांड के पास की कोशिकाओं में कैलोस बन रहा था। कैलोस ने फ्लोएम के सिरे के चारों ओर एक तश्तरी जैसा अवरोध (भित्ति) बना दिया था। फिर, अंधिकाश निर्धारित बीजांडों से वह अवरोध गायब हो गया था, और वहां मात्र एक छल्ला रह गया था जल्द ही वह छल्ला भी लुप्त हो गया था। लेकिन जो बीजांड निर्धारित नहीं हुए थे उनमें अवरोध जस-का-तस बना रहा। इससे समझ आया कि कैलोसयुक्त कोशिकाएं एक दीवार का काम करती हैं, जो फ्लोएम के पोषक तत्वों को गैर-निर्धारित बीजांडों में जाने से रोकती हैं। इस तरह पौधा गैर-निर्धारित बीजांड में अतिरिक्त पोषण जाया करने से बच जाता है। अब सवाल था कि वह क्या शय है जो निर्धारित बीजांड से कैलोस-अवरोध हटा देती है। शोधकर्ताओं की यह



तलाश एक ऐसे एंजाइम, **AtBG&ppap**, पर जाकर खत्म हुई जो कैलोस को विघटित करने (या हटाने) की क्षमता रखता है। और इसी एंजाइम को बनाने वाले जीन को अधिक सक्रिय कर कुछ फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

इस बात का खुलासा भी थेल क्रैस पर किए गए अध्ययन से हुआ। शोधकर्ताओं ने जब इस पौधे में **AtBG&ppap** एंजाइम को बनाने वाले जीन को शांत किया तो पाया कि पौधे में सभी बीजांड

भारत में यह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, यह खाली पड़े मैदान, सड़क किनारे रेललाइन किनारे, खेतों में कहीं भी उगता देखा जा सकता है, इसलिए इसे खरपतवार की तरह देखा जा सकता है हालांकि कुछ जगहों पर इसे खाया भी जाता है, थेल क्रैस पौधे की कुछ खास बातें है, एक तो इसका जीवन चक्र छोटा होता है, अंकुरण से लेकर वापस बीज बनने तक का इसका चक्र 6 हफ्तों में पूरा हो सकता है

(निर्धारित और गैर-निर्धारित) पर कैलोस भित्ति काफी हद तक वैसी की वैसी बनी रही थी। इसके कारण इस जीन के प्रभाव से मुक्त पौधों के बीज सामान्य पौधों के बीज के साइज की तुलना में 8 प्रतिशत छोटे बने थे। लेकिन जब टीएम ने इन पौधों में **AtBG&ppap** एंजाइम को जीन को अति सक्रिय किया तो पाया कि ऐसा करने पर बीज सामान्य पौधों के बीजों की तुलना में 17 प्रतिशत बड़े विकसित हुए। संभवतः इसलिए कि निर्धारित बीजांडों को कैलोस-भित्ति आसानी से टूट गई होगी और अधिक पोषक तत्व निर्धारित बीजांड तक पहुंचे होंगे। ऐसा ही उन्हीं धान के पौधों पर भी करके देखा तो उन्हें ऐसे ही नतीजे मिले- **AtBG&ppap** एंजाइम के जीन को अधिक व्यक्त करवाने पर चावल के दाने की साइज 9 प्रतिशत बढ़ गई थी। लेकिन चावल के बड़े दाने होने से शायद इसके स्वाद पर फर्क पड़े, हालांकि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने जैसी बात तो अध्ययन में सामने नहीं आई है। लेकिन बड़े बीज वाली फसलें सोयाबीन, मक्का और गेहूँ जैसी फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।

गर्मियों में रूटीन में ऐसे शामिल करें चमेली का तेल

ताजगी से भरपूर होगी आपकी सुबह

गर्मियों की सुबह चिपचिपी और उमस भरी होती है। सुबह उठने के बाद ताजगी नहीं महसूस होती है। ऐसे में अगर आप भी सुबह के समय ताजगी महसूस नहीं करते हैं, तो एक खास तेल आपकी मदद कर सकता है। जो आपकी सुबह शांति और ताजगी से भरपूर बन सकती है। चमेली के तेल को प्रकृति का खजाना कहा जाता है। इस एसेंशियल ऑयल में वह शक्ति छिपी है, जो आपको इंद्रियों को जगाता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकती हैं। ऐसे में अगर इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताते जा रहे हैं कि चमेली के तेल को अपनी रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं।



लिए आप थोड़ी सी चीना, नमक और ग्लिसरीन ले लें। फिर इसमें नींबू का रस मिलाएं और इसमें 2-3 बूंद चमेली के एसेंशियल ऑयल डालें। फिर इसे शरीर पर लगाकर 5-8 मिनट तक स्क्रब करें, जिससे डेड स्किन निकल जाएगी और खूब सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। इससे भी पॉजिटिव संचार होता है। आप चाहें तो अपने मॉइस्चराइजर में 2-3 बूंद चमेली का तेल और 1 बूंद पेचेली मिलाकर लगा सकते हैं। यह आपके मूड और स्किन दोनों को तरोताजा करेगा और यह त्वचा को जरूरतस्त चमक देगा।

चमेली एसेंशियल ऑयल वाली मोमबत्ती जलाकर आप अपने आसपास खुशनुमा माहौल बना सकते हैं और यह आपके मूड को बेहतर बना सकता है। कई बार जब हम सुबह सोकर उठते हैं, तो अजीब सी निराशा होती है। ऐसे में जब भी आप लो फील करने लगें, तो हथेली पर एक बूंद तेल लेकर इसको रब करें और सूँघें।

सप्ताह में एक बार बांडी स्क्रब का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके

बिलावल ने कबूला कड़वा सच

पाकिस्तान का इतिहास है आतंकवाद को पालना

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद को पालने की बात कबूली है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बिलावल ने माना कि पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया है। बिलावल ने कहा कि यह पाकिस्तान का एक इतिहास और यह किसी से छुपा नहीं है। इसकी वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ा है और इस समस्या से निपटने के लिए हमने सुधार किए हैं। बिलावल का यह बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद आया है। बिलावल से पहले आसिफ भी आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कबूल चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षामंत्री पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ब्रिटिश अखबार द स्काइ को दिए इंटरव्यू में यह बातें कही थीं। ब्रिटिश एंकर यल्दा



हकीम ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गति-विधियों के लिए जिम्मेदार है? इस पर उन्होंने कहा था कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। उन्होंने माना कि अगर हम, सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमलों के बाद जो हालात बने, वो न बनते तो पाकिस्तान का रिकार्ड बेदाग होता। ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना था कि आतंकियों का समर्थन करना या ट्रेनिंग देना बड़ी गलती थी। हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। बिलावल ने गुरुवार को एक बार फिर सिंधु में खून बहाने की धमकी दी। एक रैली को संबोधित

करते हुए बिलावल ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सिंधु पर हमला किया तो इससे पानी बहेगा या खून बहेगा। बिलावल ने इससे पहले पिछले हफ्ते शुक्रवार को एक रैली में कहा था कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या उनका खून। दरअसल भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को एकतरफा बताते हुए फैंसले का विरोध किया है। पहलगाम हमले को लेकर भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म करने के बाद पाकिस्तानी मंत्री और अधिकारी लगातार विवादित

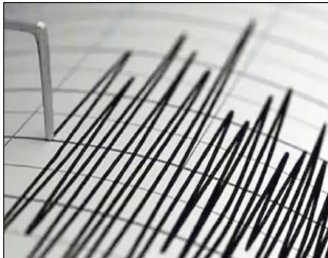
बयान दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने शनिवार 26 अप्रैल को पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में एक परेड को संबोधित करते हुए कहा कि कहा कि पहलगाम हमले का आरोप लगाकर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। पहले भी पाकिस्तान पर ऐसे हमले के आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। एक जिम्मेदार देश के तौर पर पाकिस्तान किसी भी तटस्थ और पारदर्शी जांच में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। शरीफ ने कहा कि भारत दुनिया को गुमराह कर रहा है। बिना किसी विश्वसनीय जांच और सबूत के पाकिस्तान पर झूठा आरोप लगाकर देश को बदनाम कर रहा है।

ट्रम्प ने माइक वाल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत नामित किया

न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अगला अमेरिकी राजदूत नामित किया। ट्रम्प ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अंतरिम अवधि में, विदेश मंत्री मार्को रूबियो विदेश विभाग में अपना मजबूत नेतृत्व जारी रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी काम करेंगे। पहले की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वाल्ट्ज और उनकी डिप्टी एलेक्स वॉंग दोनों के व्हाइट हाउस में गुरुवार को अपने वर्तमान पद से इस्तीफा देने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में वाल्ट्ज के नामांकन के लिए सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता है। ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में रिपब्लिकन एलिस स्टेफनिक के अपने नामांकन को 27 मार्च को वापस ले लिया।

अर्जेंटीना में 7.5 तीव्रता का आया भूकंप, सूनामी की भी चेतावनी जारी

लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी



व्युनस आयर्स। साउथ अमेरिकी देश अर्जेंटीना में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। इसके चलते सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। यह भूकंप भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे आया है। भूकंप का केंद्र अर्जेंटीना के दक्षिणी राज्य उशुआइया से 222 किमी दूर

समुद्र में डूंक पैसेज में था, जिसकी गहराई 10 किमी थी। बता दें कि डूंक पैसेज दक्षिण अमेरिका के कंप हार्न, चिली, अर्जेंटीना और अंटार्कटिका के दक्षिण शेल्लैंड द्वीपों के बीच का समुद्री इलाका है। प्रशासन

तटीय इलाकों भी को अलर्ट पर रखा गया है। चेतावनी में कहा गया है कि लहरें चिली के प्युर्टो विलियम्स तक पहुंच सकती हैं। चिली की नेशनल डिजास्टर सर्विस ने पूरे दक्षिणी तट को खाली करने के लिए कहा है। इसके लिए लोकल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने कहा कि भूकंप से निपटने के लिए देश के पास सभी संसाधन मौजूद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वो मैगलन इलाके में समुद्र तट से दूर चले जाएं। इस समय हमें अधिकारियों के निर्देशों को पूरी तरह फालो करना है। अमेरिका का सुनामी वार्निंग सिस्टम अगले एक घंटे में फिर से चेतावनी जारी करेगा।

दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के निकट हमला

यरूशलेम। इजरायल ने सीरिया में डूज समुदाय के लिए किसी खतरे को रोकने के लिए दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के निकट लक्ष्य पर हमला किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतन्याहु ने जानकारी दी है। वॉशिंगटन ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, यह सीरियाई शासन के लिए एक स्पष्ट संकेत है।

हम दमिश्क के दक्षिण में सेना की तैनाती और डूज समुदाय के लिए किसी भी तरह के खतरे को अनुमति नहीं देंगे। सीरिया के गृह

मंत्रालय ने बाद में बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि बुधवार रात से लेकर आज तक दमिश्क के निकट सीरियाई शहर साहनाया में सशस्त्र समूहों और डूज आत्मरक्षा सेनानियों के बीच झड़पें हुईं, जहां मुख्य रूप से डूज आबादी रहती है। डूज अरबों का एक जातीय-धार्मिक समूह है जो लेबनान, सीरिया, इजरायल और जॉर्डन में रहता है। दिसंबर 2024 में दमिश्क में सत्ता परिवर्तन के बाद इजरायल ने बार-बार सीरियाई डूज की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।



महामारी प्रवण वायरस: वैक्सीन प्लेटफॉर्म लॉन्च

लॉस एंजिल्स। अमेरिका ने महामारी प्रवण वायरस के लिए अगली पीढ़ी का सार्वभौमिक वैक्सीन प्लेटफॉर्म लांच किया है। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (एचएचएस) और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ने गुरुवार को जेनरेशन गोल्ड स्टैंडर्ड के लॉन्च की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह महामारी-प्रवण वायरस से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अगली पीढ़ी का सार्वभौमिक वैक्सीन प्लेटफॉर्म है। एनआईएच के अनुसार यह प्लेटफॉर्म बीटा-प्रोपियो लैक्टोन-निष्क्रिय, संपूर्ण-वायरस दृष्टिकोण पर आधारित है जो पारंपरिक वैक्सीन तकनीक का एक आधुनिक रूप है। एनआईएच ने एक विज्ञापन में कहा कि यह पहल पारदर्शिता, प्रभावशीलता और व्यापक तैयारी की ओर एक निर्णायक बदलाव का

प्रतिनिधित्व करती है जो एनआईएच के सार्वभौमिक इन्फ्लुएंजा और कोरोनावायरस टीकों के इन-हाउस विकास को वित्तपोषित करती है जिसमें बीपीएल-1357 और बीपीएल-24910 शामिल हैं। इन टीकों का उद्देश्य महामारी-प्रवण वायरस जैसे एच 5 एन 1 एवियन इन्फ्लुएंजा सहित कोरोनावायरस के कई प्रकारों के खिलाफ व्यापक-स्पेक्ट्रम सुरक्षा प्रदान करना है। एनआईएच के निदेशक डा. जय भट्टाचार्य ने कहा, जनरेशन गोल्ड स्टैंडर्ड एक आदर्श बदलाव है। यह स्ट्रेन-विशिष्ट सीमाओं से परे वैक्सीन सुरक्षा का विस्तार करता है और फ्लू वायरल खतरों के लिए तैयार करता है न केवल आज बल्कि कल भी 21वीं सदी में लाई गई पारंपरिक वैक्सीन तकनीक का उपयोग करके।



अमेरिका के साथ ईरान की फिर अनबन

तेहरान। ईरान ने कहा है कि इटली के रोम में अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का चौथा दौर मध्यस्थ ओमान के प्रस्ताव पर स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एम्माईल बाघई ने गुरुवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक बाघई ने संवादाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई तिथियों की

घोषणा बाद में की जाएगी। उन्होंने देश के 'वैध और कानूनी हितों की रक्षा करने और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों तथा आर्थिक दबाव को समाप्त करने के लिए कूटनीति का उपयोग करने के ईरान के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की।

प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल सद्भावना के साथ वार्ता में प्रवेश करने के बाद से

परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करने और अवैध प्रतिबंधों को समाप्त करने के संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देश की सैद्धांतिक स्थिति के आधार पर विशिष्ट रूपरेखाओं पर चर्चा कर रहा है, जो एक न्यायसंगत, तर्कसंगत और टिकाऊ समझौते को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिणाम-उन्मुख वार्ता के प्रति अपनी गंभीरता को प्रदर्शित

करता है। इससे पहले दिन में, ओमानी विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि शनिवार को होने वाली ईरान-अमेरिका वार्ता का चौथा दौर लॉजिस्टिक कारणां से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, पारस्पर तौर पर सहमत होने पर नई तारीखों की घोषणा की जाएगी।

हार्वर्ड यूनि: टैक्स फ्री दर्जा खत्म करेंगे: ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स फ्री संस्थान का दर्जा खत्म करने जा रहे हैं। ट्रम्प ने दृढ़ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वे इसी के हकदार हैं। इससे पहले हार्वर्ड की 2.2 अरब डॉलर फंडिंग पर रोक लगा चुके हैं। दरअसल ट्रम्प प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से यह मांग की है कि वह अक्टूबर 2023 के बाद कैंपस में हुई यहूदी विरोधी घटनाओं पर सभी सभी रिपोर्ट और ड्राफ्ट भी सरकार को सौंपे। प्रशासन चाहता है

कि इन रिपोर्टों को तैयार करने वाले सभी लोगों के नाम बताए जाएं और उन्हें संघीय अधिकारियों के इंटरव्यू के लिए उपलब्ध कराया जाए। यूनिवर्सिटी ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में केंस की किया है। यूनिवर्सिटी का आरोप है कि ट्रम्प सरकार राजनीतिक दबाव बनाकर शैक्षणिक कामकाज पर कंट्रोल करना चाहती है। हार्वर्ड ने इसे यूनिवर्सिटी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी

12 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के खिलाफ मैसेचुसेट्स की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केंस दायर किया था। को रोकनी की धमकी के खिलाफ यह केंस दर्ज किया था। दरअसल उस दौरान ट्रम्प प्रशासन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले 9 अरब डॉलर के फंड की समीक्षा कर रहा था। हार्वर्ड के प्रोफेसर ने हवाला दिया कि ट्रम्प का यह फैसला कि अमेरिकी संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट प्रथम संशोधन का उल्लंघन करता है।

विदेश मंत्रालय ने नेपाली छात्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिया इंस्टीट्यूट आफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एक नेपाली छात्रा के आकस्मिक निधन पर शोक एवं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज यहाँ एक बयान में कहा कि हम केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के एक नेपाली छात्रा के दुःखद निधन से बहुत दुःखी हैं। हम इस कठिन समय में शोक संतपन परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। इस दुःखद घटना के बारे में पता चलने के बाद विदेश मंत्रालय ओडिशा राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। ओडिशा राज्य सरकार छात्रा के परिवार को पूरा सहयोग दे रही है। वर्तमान में ओडिशा पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण को बहुत गंभीरता से लेती है।

इस साल भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता करेंगे



नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस

शेफकोविक ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों के समाधान के लिए एक दूरदर्शी और ठोस वार्ता की और 2025

के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए संपन्न करने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की। बातचीत में दोनों नेताओं ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेएन द्वारा फरवरी 2025 में यूरोपीय संघ के आयुक्तों के कॉलेज की नई दिल्ली की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दोनों पक्षियों के संबंधों को दी गई रणनीतिक दिशा पर आधारित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गोयल की यूरोपीय यात्रा के निष्कर्ष पर शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उच्च स्तरीय सहभागिता इस बात को रेखांकित करती है कि दोनों साझेदार एक व्यावसायिक रूप से सार्थक, पारस्परिक रूप से लाभकारी, संतुलित और निष्पक्ष व्यापार साझेदारी बनाने के

लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं जो आर्थिक सशक्त और समावेशी विकास का समर्थन करती है। गोयल की यूरोपीय संघ के साथ इस बातचीत में एफटीए वार्ता के विभिन्न पहलुओं पर हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया और मासिक बैठकों और निरंतर आभासी सहभागिता के माध्यम से चल रही गति को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान और व्यावहारिकता की भावना से लंबित मुद्दों को हल करने के अपने उद्देश्य को दोहराया, जिसमें 12-16 मई 2025 को नई दिल्ली में होने वाला अगला दौर भी शामिल है। विज्ञापन में कहा गया है कि भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि व्यापार वार्ता में सार्थक प्रगति के लिए प्रशुल्क कटौती चर्चाओं के साथ-साथ गैर-प्रशुल्कीय बाधाओं



पर भी समान ध्यान देने की आवश्यकता है और नियामक ढांचे को समावेशी, अनुपातिक होना चाहिए तथा व्यापार को प्रतिबंधित करने से बचना चाहिए। भारत-यूरोपीय संघ एफटीए डिजिटल संक्रमण का समर्थन करके, विविध और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर वैश्विक वाणिज्य की उभरती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने की आकांक्षा रखता है। विज्ञापन के अनुसार, दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की कि एक बार समझौता हो जाने पर, यह व्यापक भारत-यूरोपीय संघ रणनीति का साझेदारी के एक परिवर्तनकारी स्तंभ के रूप में काम करेगा, बाजार में प्रवेश की सुगमता को बढ़ाएगा, नियामक सहयोग का समर्थन करेगा और दोनों पक्षों में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।

स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 341.1 अरब डॉलर से 13.6 प्रतिशत अधिक है। मार्च 2025 में, सेवा निर्यात 35.6 अरब डॉलर रहा, जो मार्च 2024 में 30.0 अरब डॉलर की तुलना में 18.6 प्रतिशत की साल दर साल वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष सकल निर्यात 778.1 अरब डॉलर के बराबर था। वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञापन में कहा देश के व्यापार की प्रगति की राह में एक नया मील का पथर स्थापित करता है। वर्ष 2024-25 में, पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर व्यापारिक निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 374.1 अरब डॉलर हो गया, जो 2023-24 में 352.9 अरब डॉलर से 6.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

गिफ्ट निफ्टी ने अप्रैल 2025 में रचा नया कीर्तिमान मुंबई। गिफ्ट निफ्टी ने अप्रैल 2025 में 100-93 अरब डॉलर का अब तक का सबसे उच्च मासिक कारोबार हासिल करके एक नया कीर्तिमान बनाया है। यह उल्लेखनीय यह कीर्तिमान सितंबर 2024 में 100.7 अरब डॉलर के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई है। यह भारत की विकास कहानी के लिए एक बेंचमार्क के रूप में गिफ्ट निफ्टी में बढ़ती वैश्विक रुचि और विश्वास को दर्शाता है। एक विज्ञापन में कहा गया है कि हमें गिफ्ट निफ्टी की सफलता को देखकर खुशी हुई है।